



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 3, 2006/माघ 14, 1927

No. 24]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 3, 2006/MAGHA 14, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच प्रारंभ अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2006

विषय : चीन जन गण के मूल के अथवा वहां निर्यातित ड्राई सेल बैटरी पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में अन्तिम पुनरीक्षा का प्रारम्भ।

सं. 53/1/2000-डीजीएडी.— निर्दिष्ट प्राधिकारी ने, वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर क्षति का आकलन एवं शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के मद्देनजर चीन जन.गण. (जिसे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'ड्राइसेल बैटरी' जो उपशीर्ष 8606.10 के तहत आता है, के आयातों पर अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी। प्रारंभिक जांच-परिणामों को दिनांक 24 जनवरी, 2001 की अधिसूचना सं० 53/1/2000-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित किया गया और संबद्ध माल पर दिनांक 6 फरवरी, 2001 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं० 14/2001-सीमाशुल्क द्वारा अनन्तिम शुल्क लगाया गया। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना सं० 51/1/2000-डीजीएडी द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2001 को अंतिम जांच-परिणाम जारी किए और सीमाशुल्क विभाग द्वारा दिनांक 2 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं० 84/2001-सीमाशुल्क द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगा दिया गया।

विचाराधीन उत्पाद:

- मौजूदा याचिका में विचाराधीन उत्पाद ड्राइ बैटरियां (विशिष्टतया प्राइमरी सेल तथा बैटरियां) हैं जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची 7 के सीमाशुल्क उपशीर्ष 8506.10 के तहत वर्गीकृत हैं। यह वर्गीकरण संकेतात्मक

मात्र हैं और इनकी मौजूदा जांच के दायरे पर कोई भी बाध्यता नहीं है। ये बैटरिया विभिन्न किस्मों एवं आकारों में उपलब्ध रहती हैं। किंतु, "एए", "यूएम3" दोनों कागज तथा धातु (दोनों ही हैवी ड्यूटी तथा सुपर हैवी ड्यूटी) जैकेटेड रूप में जिक कार्बन पेंसिल बैटरियों जिन्हें तकनीकी एवं वाणिज्यिक दृष्टियों से "आर6" के नाम से जाना जाता है, इस जांच के दायरे में शामिल हैं। बैटरियों की दूसरी किस्में जैसे अल्कालीन बैटरियों, रिचार्जबल बैटरियां, आदि मौजूदा जांच के दायरे में नहीं हैं। विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है जैसाकि दिनांक 13 जुलाई, 2001 के अंतिम जांच-परिणामों में यथाअधिसूचित हैं।

3. ड्राइ सेल बैटरी के प्रयोग का एक विस्तृत क्षेत्र है और इनका प्रयोग मूल रूप से फ्लैशलाइटों, ट्रांजिस्टरों, खिलौनों, दीवार तथा टेबल घड़ियों, टेप रिकार्डरों, वाकमैन, सी.डी.प्लेयरों, रिमोट, कैमरों, अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों, डाक तथा तार विभाग, रक्षा तथा पुलिस विभागों में उनकी बेतार प्रणालियों, सिग्नलिंग के लिए रेलवे और मौसम विज्ञान के अनुप्रयोगों, आदि में किया जाता है।

नियम 2(घ) के आशय के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित माल संबद्ध देश से आयातित माल के "समान वस्तु" हैं।

जांच प्रारंभ:

4. सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाई गई नियमावली में प्राधिकारी से अपेक्षा है कि वह पाटनरोधी शुल्क जारी रखे जाने की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा करे। निर्दिष्ट प्राधिकारी समझता है कि अनुशंसित पाटनरोधी शुल्क की अन्तिम समीक्षा करना यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9 क (5) और उसके तहत बनाई गई नियमावली के उपबंधों के अधीन ऐसे समय पर यथोचित रहेगा। मै0 एवरेडी इण्डस्ट्रीज इंडिया लि0, मै0 निप्पो बैट्रीज कंपनी लिमिटेड की ओर से एसोसिएशन ऑफ इंडियन ड्राइ सेल मैन्यूफैक्चरर्स ने एक ऐसा आवेदन-पत्र दर्ज कराया है जिसमें उन्होंने चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध माल पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा की आवश्यकता को साबित किया है और अनुरोध किया है कि ऊपर उल्लिखित अधिसूचनाओं के तहत संबद्ध माल पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखा जाए।

शामिल देश:

5. मौजूदा जांचों में शामिल देश चीन जन.गण. (जिसे इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) है।

प्रक्रिया:

6. दिनांक 13 जुलाई, 2001 की अधिसूचना सं0 53/1/2000-डीजीएडी द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच-परिणामों की समीक्षा के निर्णय और दिनांक 2 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं0 84/2001 द्वारा लगाए गए अंतिम शुल्क को देखते हुए, प्राधिकारी एतद्वारा इस आशय की समीक्षा हेतु जांच प्रारंभ करता है कि क्या सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण और क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ड्राइसेल बैटरियों के आयातों पर लगे पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप पाटन तथा क्षति जारी रहेगी अथवा उनकी पुनरावृत्ति होगी।
7. इस समीक्षा में दिनांक 13 जुलाई, 2001 की अधिसूचना सं0 53/1/2000-डीजीएडी के सभी पहलू कवर किए गए हैं।

जांच अवधि:

8. मौजूदा जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (जिसे इसके बाद जांच अवधि कहा गया है) दिनांक 1 अप्रैल, 2004 से 30 सितंबर, 2005 तक के लिए है। लेकिन, क्षति जांच अवधि में वर्ष 2001-2002 से 2004-2005 तक और जांच अवधि का समय कवर होगा।

9. जानकारी प्रस्तुत करना:

संबद्ध देश के निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास/उच्चायोग की मार्फत उनकी सरकार, संबंधित ज्ञात भारतीय आयातकों तथा प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग से अलग-अलग अनुरोध किया जा रहा है कि निर्धारित रूप तथा तरीके में नीचे दिए गए पते पर संगत जानकारी प्रस्तुत करें और अपने-अपने विचार बता दें:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी,
बाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
बाणिज्य विभाग,
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी),
कमरा सं० 240, उद्योग भवन,
नई दिल्ली-110011.

10. कोई अन्य पक्षकार भी इस जांच के संगत निवेदन नीचे निर्धारित समयावधि के भीतर निर्धारित रूप तथा तरीके में कर सकेगा ।

समय-सीमा:

12. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी इच्छुक पक्षकार अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकेगा। सभी इच्छुक पक्षकार उपरोक्त नियमावली के नियम 7(1) के अनुसार एक-एक गोपनीय तथा अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करेंगे । यदि कोई इच्छुक पक्षकार यथोचित समयावधि के भीतर आवश्यक जानकारी देने की मनाही करता अथवा वह उसे प्रदान नहीं करता है तो तब प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार अपने जांच-परिणाम लिख देगा और जैसा वह उचित समझता है वह केन्द्रीय सरकार को वैसी सिफारिशें कर सकेगा ।

क्रिस्टी एल. फर्नान्डेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd February, 2006

Subject : Initiation of Sunset Review regarding anti-dumping duty imposed on Dry Cell Battery originating in or exported from China PR.

No. 53/1/2000-DGAD.—The Designated Authority, having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, recommended imposition of provisional Anti Dumping duty on imports of “Dry Cell Battery” (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR (referred to as subject country) falling under Sub-heading 8506 10. The preliminary findings were published vide Notification No 53/1/2000-DGAD dated 24th January, 2001 and provisional duty was imposed on the subject goods vide Customs notification No. 14/2001-Customs, dated the 6th February, 2001. The Designated Authority came out with final findings on 13th July 2001 vide notification no 53/1/2000-DGAD and definitive anti dumping duty was imposed by Customs as per notification No. 84/2001-Customs dated 2nd August 2001.

Product under Consideration:-

2. The product under consideration in the present petition is dry batteries (specifically primary cells and batteries) which is classified under custom sub-heading 8506 10 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation. The batteries are available in various types and sizes. **However Zinc Carbon pencil batteries technically and commercially known as “R6”, “AA”, “UM3” both in paper and metal (both heavy duty and super heavy duty) jacketed form are within the scope of investigation.** Other types of batteries such as, alkaline batteries, rechargeable batteries etc are beyond the scope of the present investigation. The scope of the product under consideration is the same as notified in the final findings dated 13th July, 2001.

3. Dry Cell Battery has a broad spectrum of uses and is primarily used in Flashlights, Transistors, Toys, Wall and table clocks, Tape Recorders, Walkman, CD players, Remotes, Cameras, Other electronic equipment, Post & Telegraph, Defense and police for their wireless systems, Railways for signaling and Meteorological applications etc

The goods manufactured by the domestic industry are 'like articles' to the goods imported from the subject country within the meaning of Rule 2(d).

Initiation:-

4. The Customs Tariff (Amendment) Act 1995 and the Rules made there under require the Authority to review from time to time the need for continuance of anti dumping duty. The Designated Authority considers that the sunset review of the Anti-Dumping Duty recommended would be appropriate at this stage under the provision of section 9A (5) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 as amended and the Rules made thereunder. Association of Indian Dry Cell Manufacturers on behalf of M/s Eveready Industries India Ltd., M/s Nippo Batteries Company Limited and M/s Panasonic Battery India Company Limited has filed an application substantiating the need for review of the antidumping duty imposed on the subject goods originating in or exported from China PR and have requested for continuation of the anti-dumping duty imposed on subject goods under the above mentioned notifications for a further period of 5 years.

Countries Involved:-

5. The country involved in the present investigations is China PR (referred to as subject country hereinafter).

Procedure:-

6. Having decided to review the final findings notified vide No. 53/1/2000-DGAD dated 13th July 2001 and final duty imposed by Notification No. 84/2001-Customs dated 2nd August 2001, the Authority hereby initiates investigations to review whether cessation of antidumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury on imports of Dry Cell Batteries originating in or exported from subject country, in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment & Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995.

7. The review covers all aspects of Notification 53/1/2000-DGAD dated 13th July 2001.

Period of Investigation:-

8. The period of investigation (hereinafter referred to as POI) for the purpose of present investigation is 1st April 2004 to 30th September 2005. The injury investigation period will however cover the periods from 2001-2002 to 2004-2005 and the POI.

Submission of Information:

9. The exporters in subject country, their government through their Embassy/High Commission in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

The Designated Authority,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties, (DGAD),
Room No. 240,
Udyog Bhavan,
New Delhi-110011

10. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Time Limit:-

11. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

Inspection of Public File:-

12. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties. All interested parties shall provide a confidential and non-confidential summary in terms of Rule 7 (2), for the confidential information provided as per Rule 7 (1) of the Rules supra. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

CHRISTY L. FERNANDEZ, Designated Authority